12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported preparations by Election Commission for mid-term Parliamentary Elections

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"निर्वाचन आयोग द्वारा बार-बार की गई अधिघोषणायें और देश के मध्यावधि संसदीय चुनावों के लिए जल्दी में की जा रही तैयारियां ."

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : Mr. Speaker Sir, Under Article 324 of the Constitution, the Election Commission is vested with the superintendence, direction and control of, *inter alia*, the preparation of electoral rolls. It is, therefore, the constitutional obligation of the Election Commission to keep the electoral rolls ready at any point of time. Section 21 (2) (b) of the R. P. Act, 1950 provides for the revision of electoral rolls in any year, if so directed by the Election Commission.

With a view to meet the criticism of the electoral process being tardy and time consuming, a meeting of the Chief Electoral Officers of all the States and Union territories was held on the 5th November, 1969, and a decision was taken to revise the electoral rolls throughout the country within a period of two months and a programme was chalked out and finalised. The work of revision is now going on in full swing in all the States and Union territories. In chalking out its programme the Election Commission has not done anything more than what was thought necessary in the discharge of its constitutional and legal obligations and functions. The allegation that there have been frequent pronouncements and hasty preparation for mid-term parliamentary elections is not well-founded. If the Election Commission takes a long time in the revision of electoral rolls, as has been the practice hitherto, it is accused and criticized of tardy electoral process and undue delay. The Election Commission, therefore, is trying to make a new experiment for expeditious revision of the rolls. The Chief Election Commissioner has emphasised that the revision is not going to be a hasty one. Adequate steps are being taken to put efficient staff on the work throughout the country.

Shortly after the conclusion of the Chief Electoral Officers' Conference on the 5th November, 1969, a press note was issued by the Election Commission in which it was specifically mentioned that "the question of quick revision of electoral rolls and keeping the election machinery in good gear should not be related to any event or a situation."

श्री शिव चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है मैं अखबारों को पढ़कर उद्धरण नहीं देना चाहता – कि बार बार एलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेटमेंट, वक्तव्य आ रहे हैं कि इस देश में शार्ट नोटिस पर लोक सभा के लिए आम चुनाव कराये जायेंगे ।...(व्यवधान)...एलेक्शन कमीशन के इन वक्तव्यों से देश में एक पैनिक फैल रहा है, एक आतंक फैल रहा है । जबकि अभी संसद मौजूद है तब इस प्रकार की कल्पना करके कि वह भंग हो रही है, सारे देश में एक आतंक फैलाया जा रहा है । दूसरी बात यह है कि जो कानून मन्त्री हैं उनके जो पुराने वक्तव्य हैं वह इस सदन को गुमराह करने के लिए है –यह कैसे, आप जरा सुनें । यहां पर ये कहते हैं कि एलेक्टोरल रोल्स रिवाइज करने में समय लगता है और अब तक जो सुस्ती हुई है और जिसके मुताल्लिक आलोचना होती है, वह आलोचना न हो इसलिए एलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सन् 967 में जो आम चुनाव हुए तब से अब तक एलेक्टोरल रोल्स का काम नहीं हो सका और अभी 5 नवम्बर को जो एलेक्शन कमीशन की बैठक हुई उसमें यह आदेश दिया गया है कि दो महीने में तमाम रिवीजन हो जाये और आम चुनाव के लिए तमाम तैयारियां हो जाय तो पिछले ढाई

[श्री शिव चन्द्र झा]

साल में एलेक्शन कमीशन ने यह रिवीजन का काम क्यों नहीं किया और उसके लिए आपने कौन से आदेश दिये हैं ? या जैसा कि आप खुद कहते हैं कि जन्तर मन्तर कांग्रेस मे जितने काम हुए हैं वे इल्लीगल हैं इसलिए क्या हम यह समझें कि सिंडीकेट वाले जोकि डिफेक्टर्स हैं उनके एलेक्शन्स को वायड करके उनकी जगह पर दूसरे नये एलेक्शन्स कराये जायेंगे ?...(व्यवधान)...

मैं साफ शब्दों में दो बातें जानना चाहता हूँ। एक तो यह कि पिछले ढाई सालों में कौन सा काम किया गया और दूसरे, क्या सिन्डीकेट के मेम्बरों के एलेक्शन को वायड करके उनकी जगह पर दूसरे नये एलेक्शन्स किये जायेंगे ?

SHRI B. P. MANDAL *rose*—

MR. SPEAKER : This is a calling attention motion in the names of two hon. members. The hon. member' is not one of them.

SHRI B. P. MANDAL (Madhapur) : I rise to a point of order.

MR. SPEAKER : No.

I may add that a number of members have enquired from me also about this. If this is a normal routine whereby every year the voters' lists are revised, it is one thing. But every time a statement comes that the Election Commissioner is ready to hold electlons within one month and so on ; again in the next week another statement comes that preparations to hold elections are complete. Will the hon. Minister make it clear whether this is just a routine revision of the rolls or it is proposed to hold elections earlier so that we shall also get ready for it ?

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : One thing more. Let them dissolve Parliament and also dissolve the Government and let them go to the electorate ; let us all go to the electorate to decide.

MR. SPEAKER : I have asked him to clarify whether this is a normal routine revision as has been done in previous years or some instructions have gone out so that members may get ready for the coming events. It might concern him also.

SHRI GOVINDA MENON : I want to state categorically that no instruction has been given in this respect and such revision as is going on...

MR. SPEAKER : But it is extraordinary this time.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : This is not a routine revision.

SHRI RABI RAY (Puri) : This is not a routine revision.

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : As I said, this is a call attention in the names of two members. Only they will ask questions.

श्री शिव चन्द्र झा : इन्होंने साफ नहीं किया कि एलेक्शन कमीशन ने पिछले ढाई साल में यूजुअल काम क्या किया और अब जल्द से जल्द दो महीने के अन्दर क्यों करना चाहते है ?...(व्यवधान)...इसका जवाब दें। अब कौन सा आदेश दिया गया है कि दो महीने में काम किया जाये ? क्या हम यह समझ लें कि इन्होंने पहले कुछ नहीं किया इसलिये अब दो महीने में करने जा रहे हैं।...(व्यवधान)...

MR. SPEAKER : There are two Jhas. I was calling the other hon. member, Shri Bhogendra Jha.

SHRI KANWARLAL GUPTA : Why have bye-elections been postponed ?

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : There is no justification for postponing bye-elections.

SHRI MADHU LIMAYE (Mongyr) : On a point of order.

MR. SPEAKER : The question of postponement of bye-elections does not arise out of this.

I have told him what the Members have told me when they wanted to know about it from me. I am also unaware ... as any one of them.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप के प्रश्न का भी जवाब नहीं मिला है। उन्होंने भी दो बार पूछा है लेकिन वह इस का जवाब नहीं दे रहे हैं।

SHRI GOVINDA MENON : In the right of the statements repeatedly made I want to state categorically that no instructions have been given in this matter to the Chief Election Commissioner and there is no contemplation of mid-term election.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Then what is the need for the Election Commission to say that they can hold a mid-term election at short notice.

श्री मधु लिमये : सवाल क्या है और जवाब क्या है।

अध्यक्ष महोदय श्री शिवचन्द्र झा।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय मैं एक प्वाइन्ट श्रोफ श्रार्डर उठाना चाहता हूँ। श्री शिव चन्द्र झा ने पूछा है कि एलैक्टोरल रोल्स...

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे सवाल पूछने का आदेश दिया है और मैं आप के आदेश पर ही सवाल पूछने के लिये खड़ा हुआ हूँ तो फिर इस तरह से बीच में एक माननीय सदस्य द्वारा आप के आदेश की अवहेलना करना कहां तक उचित होगा ?

MR. SPEAKER : He is on a point of order.

श्री बि० प्र० मंडल : मेरा भी एक प्वाइंट श्रोफ श्रार्डर है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठें।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय...

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कैसे चलेगा ? क्या सदन में जो एक कायदा और व्यवस्था है उसे चलने नहीं दिया जाएगा ? मैं पिछले ढाई साल से इस सदन में एक मर्यादा व व्यवस्था के अंदर रखते हुए आचरण करता रहा हूँ लेकिन मुझे आज यह दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ सदस्य इस तरह से अध्यक्ष की अवहेलना करने और प्रोसीडिंग्ज में बाधा डालना एक अपनी इजारेदारी समझते हैं। इस से क्या अब यह समझा जाय कि इस सदन में ऐसे सदस्यों को अध्यक्ष की अवहेलना करने सामान्य कार्यपद्धति में बाधा डालने की इजाजत दी जायगी और उन्हें रोका नहीं जायगा ? इस तरह से जो लोग यहाँ एक सदन् की प्रतिष्ठा के अनुरूप कायदे के मुताबिक व्यवहार करना चाहते हैं उन के साथ नाइंसाफी करनी होगी क्योंकि इस तरह से उन्हें उनके बोलने के हक में इस तरह से कुछ सदस्यों द्वारा बाधा डाल कर रोका जायगा। दरअसल ये लोग इनकिलाबी बनने का ढोंग रचते हैं हालांकि इनकिलाबी वह है नहीं, खाली वह अखबार में अपना नाम छपवाने के लिए और चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए उत्सुक रहते हैं।

श्री मधु लिमये : यह दूसरों के ऊपर इस तरह से बहुत बेजा आरोप लगा रहे हैं जोकि कदापि वांछनीय नहीं है।

श्री रबि राय : अध्यक्ष महोदय ने स्वयं श्री मधु लिमये को प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाने की इजाज़त दी है।

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर...

श्री भोगेन्द्र झा : ऐसे नहीं चलेगा।

MR. SPEAKER : The usual practice is that when a Member is on a point of order the Member's speech is interrupted, so that the chair can listen to the point of order. In this case Mr. Jha thinks that Mr. Madhu Limaye got up to interrupt him. I do not think so. Let him first put his question.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : When Mr. Mandal raised a point of order, you did not allow him.

MR. SPEAKER : He wanted to ask a question. Let Mr. Limaye wait for a second. Let Mr. Jha complete what he wants to say ; it is my request to them. It makes no difference. Let him complete his question.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो केवल श्री शिव चन्द्र झा के प्रश्न के बारे में प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर उठा रहा हूँ...

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय इस तरह से नहीं चलेगा। तीन बार आप ने मुझे सवाल पूछने का आदेश दिया लेकिन वह सदस्य इस तरह से बीच में खड़े होकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या इस सदन में कोई कायदा नहीं चलेगा ? अगर ऐसे चलने दिया जाता है तो मैं अपने मतदाताओं से यह कहने के लिए विवश हूँगा कि यहां सदन में केवल वह लोग जो हल्ला करते हैं, उन की बात सुनी जाती है लेकिन जो लोग कायदे के मुताबिक व्यवहार करते हैं उनकी अनसुनि कर दी जाती है।

MR. SPEAKER : The position is clear. He has accepted my request. Let him say what he wants to say.

SHRI D. N. TIWARI (Gopalganj) : I am sorry to interrupt you. But at the outset Mr. Mandal raised a point of order ; you did not allow him to do so.

MR. SPEAKER : He wanted to ask a question, not raise a point of order.

श्री मधु लिमये : मैं केवल श्री शिवचन्द्र झा के प्रश्न के बारे में प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर उठा रहा हूँ। जाहिर है कि उनका प्रश्न खत्म होने पर और दूसरा शुरू हो जाने पर मैं पहले प्रश्न के बारे में कैसे प्वाएंट ग्रोफ ग्रार्डर उठा सकता हूँ ? मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं और न ही जैसा श्री भोगेन्द्र झा समझ रहे हैं मैं उन्हें कोई टोक रहा हूं ; मैं आधे सैकेंड में खत्म कर दूंगा।

MR. SPEAKER : I request Mr. Limaye to wait.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, प्वाएंट ग्राफ ग्रार्डर में आप से पूछ रहा हूँ ;

श्री भोगेन्द्र झा : मैं केवल अध्यक्ष महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि उन का आदेश यहां चलेगा अथवा नहीं ?

MR. SPEAKER : He was on his legs when I got up ; then he sat down. In the meanwhile Shri Limaye got up to raise a point of order. He thinks that Mr. Limaye is interrupting him. I may assure him that Mr. Limaye is not interrupting him. Anyway let him finish ; his is the second name in the calling attention motion. After that I shall allow Mr. Limaye to state his point of order.

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने सदन के सामने जो वक्तव्य दिया है उससे बातें साफ नहीं होती हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी ओर से कोई लिखित आदेश चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। सवाल यह है कि कोई जबानी आदेश गया है या नहीं यह बातें सुनी जा रही है कि देश में जितने उपचुनाव होने वाले थे वह सभी स्थगित कर दिये गये है और अब कोई भी उप चुनाव चाहे विधान सभा का या लोक सभा का फरवरी के पहले नहीं होने जा रहा है। यह अपने में एक असाधारण घटना है कि जितने उपचुनाव विधान सभा या लोकसभा के होने वाले थे उन के होने की बात तय हो गई थी वह सभी स्थगित कर दिये गये हैं ; जब पूरे एलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन पूरा हो जायेगा उसके बाद वह होंगे तो इस का क्या कारण है ?

दूसरे 5 नवम्बर को जब यह सम्मेलन बुलाया गया तो उसी मौके पर जबकि कुछ सदस्य सरकारी दल के उससे अलग होकर सरकार को गिराने की बात प्रधान मंत्री को

निष्कासित करने की बात कर रहे थे तो या तो सरकार या आदेश चुनाव आयोग ने माना या नहीं तो अभी सरकारी दल का एक हिस्सा जो विरोधी दल में शामिल होने जा रहा है, वह है नहीं चूंकि नाम उसने अभी बदला नहीं है, नाम अभी वही है. अलबत्ता अगर उसका बाजाब्ता नामकरण हो जाय हम समझ सकते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा वह उस रास्ते में हैं, अभी सुलह की बात कर रहे हैं, अगर वह हो जाय तो क्या उनके आदेश पर जो उसमें भूतपूर्व मंत्री हैं, उस समय मंत्री भी थे तो इनके आदेश से अगर नहीं हुआ है तो फिर क्या उन के आदेश से ऐसा हुआ है कि प्रधान मंत्री अगर एक दल से निष्कासित हो जांय तो सदन में बहुमत रहे या न रहे फिर वह मध्यावधि चुनाव होगा।

तीसरे जनतंत्र का तकाजा है कि बीच में मध्यावधि चुनाव हों उसमें हमें ऐतराज नहीं। ऐसा मौका आ सकता है. आना चाहिए भी कि पांच साल के भीतर वैसी स्थिति पैदा हो जाय तो नये चुनाव हों उसमें घबड़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है जो सदन ने अपनी प्रतिक्रिया 17 तारीख को जाहिर की है उस पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग द्वारा उपचुनावों का स्थगित करना और 35 दिन में यह चुनाव पूरे कर लेने का ऐलान करना आखिर इस तरह के 35 दिन में उसके द्वारा चुनाव पूरे कर लेने का क्या कारण था ? यह बयान दिया था कि 35 दिन के अन्दर चुनाव पूरे कर लेंगे। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी ? अगर यह सरकार की राय के खिलाफ है तो मैं जानना चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार की स्थिति क्या है ?

MR. SPEAKER : Shri Madhu Limaye wanted to raise a point of order.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, the Minister will forget the question.

श्री मधु लिमये : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री शिवचन्द्र झा ने जो प्रश्न पूछा था मंत्री महोदय ने उसका जवाब नहीं दिया है। श्री शिव चन्द्र झा ने पूछा था......

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) : मैं भी प्वाइंट आफ आर्डर रेज करूंगा।

श्री रवि राय : आप क्या प्वाइंट आफ आर्डर रेज करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, आप ने श्री मधु लिमये को बुलाया है आप उनको सुनिये।

श्री मधु लिमये : क्या माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब नहीं आना चाहिए ?

SHRI GOVINDA MENON : Sir, as you know, the Chief Election Commissioner is an independent authority. I want to state once again that no instruction either written or verbal.

AN HON. MEMBER : Or private.

SHRI GOVINDA MENON : Verbal may be private also. No instruction has been given either written or verbal to the Chief Election Commissioner with respect to this matter. The conference held on the 5th November was held at the instance of the Chief Election Commissioner. In fact, I came to know about that conference only after I received the papers for drafting this answer to the Calling Attention motion. This matter of revision of the electoral rolls is being done in the routine fashion... (*Interruption*) the preparation of the electoral rolls being a duty cast upon the Chief Election Commissioner by the constitution, he is only discharging his duties.

As stated in the written answer which I read out, previously there has been delay in the matter of revision of the electoral rolls and that has come up for criticism often ; on account of the electoral rolls not being ready, the elections had to be postponed particularly in States where the President's rule was imposed. I want to say once again that this matter is dealt with by the Chief Election Commissioner under the Constitutional and legal authority vested in him.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : On a point of order.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, he has not replied to it.

SHRI BAL RAJ MADHOK : He has misled the House.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : (Chittoor) : Sir, a point of order.

MR. SPEAKER : All are points of order !

SHRI B. P. MANDAL : Sir, there is my point of order.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Are you satisfied with his answer, Sir ? We are not satisfied.

SHRI B. B. MANDAL : Before I place my point of order, I crave your indulgence to hear me patiently and allow me to make out my point.

MR. SPEAKER : I just want to hear your point of order in two seconds. No more speech.

SHRI B. P. MANDAL : In two seconds it is not possible. The point is, in every parliamentary democracy, in every House, the seating arrangement is like this. There is one seat for the Minister. *(Interruption)*

MR. SPEAKER : There is no point of order.

SHRI B. P. MANDAL : Sir, as a protest I am walking out. I know no less than you do about the functioning of parliamentary democracy. The only difference is that you were in Punjab and I was in Bihar.

(Shri B. P. Mandal then left the House)

MR. SPEAKER : I am very sory this has happened. He is a former Chief Minister of a State. I am very sorry he has behaved like this. The subject matter which he raised is entirely different from the one which the House was considering. If he had raised it at the proper time, I would have considered it. Now, what is the point of order of Shri Madhok ?

SHRI BAL RAJ MADHOK : My point of order is this. The hon. Minister is either not well-informed or he is deliberately misleading the House. The Election Commission has issued orders, in a letter dated 15th November, which reached our office on the 18th November, in which it has been stated that the revision of the electoral rolls in Delhi will be completed by the 30th November. For that purpose a large staff has been recruited. The letter clearly says that the revision of electoral rolls has to be completed by 30th November. In the light of that, how can he say that no instructions have been issued like that.

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : My point of order is that a crucial question which has been asked earlier has not been answered about the Election Commission being prepared to conduct a general election within 35 days. Secondly, there is the announcement of the postponement of the bye-elections for a particular period. These announcements of the Commission, as you have yourself rightly observed, give some impression. I want to know whether an enquiry was made by the Government why these two decisions were taken. If he has got any information, he may give it.

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे इतना ही कहना है कि पिछले पन्द्रह दिनों से एलेक्शन कमीशन के बयान आ रहे हैं और जो काम हो रहे हैं वह यह इम्प्रेशन दे रहे हैं कि कोई मिड-टर्म जनरल एलेक्शन होने वाले है और जैसा मंत्री महोदय ने कहा यह रुटीन चेक-अप है, यह ठीक नहीं है। सिर्फ आम चुनाव होने के पहले इस तरह से लार्ज स्केल पर एलेक्टोरल रोल बदले जाते है, हर साल नहीं बदले जाते। यह जवाब ठीक नहीं है। या तो आप इस पर डिस्कशन करवाइये या फिर मंत्री महोदय से कहिये कि वह ठीक जवाब दें पूछ कर। उनके जवाब से हमारी तसल्ली नहीं हुई।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Sir, I would request you to allow a half an hour discussion on this bungling by this Minister over this issue.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं।

MR. SPEAKER : I stick to my decision that only those who have given notice of their names can ask question on a Calling Attention Notice. But if hon. Members are raising points of orders I cannot help it. But the points of orders should relate to procedural irregularities and not for eliciting information.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : The reply of the Minister is inadequate. So, would you permit a short duration discussion on this issue ? I am sure you will appreciate that the urgency is there.

MR. SPEAKER : All of you are aware of the procedure for having a half-an-hour discussion.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : That is only in respect of questions. Here it is a Calling Attention Notice.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It will come under rule 193.

MR. SPEAKER : I will discuss it with the Minister and see if he is prepared to have a discussion... *(interruptions)*. During the last few days at least half of my visitors are asking this question whether I know something about it. I hope the Minister will take note of the feelings of the House.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : You should allow a discussion. What is the harm ?

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी (श्रीनगर) : 193 के तहत हम डिसकशन चाहते हैं। कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं होनी चाहिए ।

(شری غلام محمد بخشی (سرینگر) : ۱۹۳ کے تحت ہم ڈسکشن چاہتے ہیں کوئی ڈفیکلٹی اس میں نہیں ہونی چاہئے)

MR. SPEAKER : If you give notice, I will certainly consider it and try to accommodate you.

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : इलेक्शन कमीशन को बरखास्त किया जाये। वह इंदिरा का पिट्ठू है ।

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : Sir, before you proceed to the next item I have a submission to make regarding a serious matter on which I have met you in your chamber. I have also written a detailed letter to you. I am referring to the seating arrangements in the House. My point is that a spilt away part of the Congress is given the status of the main opposition party in the House, which is contrary to the rulings given by Shri Mavalankar and the practice so far followed.

MR. SPEAKER : I have received his letter.

SHRI NAMBIAR : If they have left another party and formed a group they may be given a seat as a group, but not the main opposition and thereby shunting about the other opposition groups for which they have no right... *(interruptions)*. It cannot and should not be done. I have with me a rulling of the Speaker... *(Interruptions)*

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Let us meet according to the Soviet or Chinese practice.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : Sir, I want to raise a point of order. But you are on your legs.

MR. SPEAKER : Does it mean that when others are standing I have to sit down to enable them to raise points? When I am on my legs others will have to resume their seats.

Shri Nambiar has written to me about the seating arrangements provided to the new party. I may inform him that I am considering this radical phenomenon that when an organism is cut into two whether both of them are alive or both of them are dead. If you say one is alive, I have to consider which one.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : The difficulty is that both of them are alive and we are sandwiched between them.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : Sir, only one party can have one symbol. How can you allow both parties the same name and the same symbol ? If you allow that, it is very unfair.

DR. RAM SUBHAG SINGH : I have been listening to this argument since yesterday. We belong to the parent organisation. the Indian National Congress. So, we are the real Congress Party in Parliament and we alone should be allowed to have this name...*(interruptions)* We have inherited this party and, consequently, the name also. I want to tell my friends that no party is going to be given a name at the insiance of another party.. *(interruptions* We have the right to have that name. As I said earlier, we belong to the parent organisation... *(Interruptions)*

These fellows who are objecting to it... *(in erruption)*

SOME HON. MEMBERS : He must withdraw this.

SHRI UMANATH : It is idiotic of him to say like that... *(interruption)*. If he says, "these fellows", I say, he is an idiot... *(intetrnption)*

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East) : He is a barbarian...... *(Interruption)*.

Does he think that others are also like him ?

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, I rise on a point of order.

MR. SPEAKER : Please do not provoke him.

SHRI NAMBIAR : There is a ruling here. There is no question of any provocation.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) *rose*—

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Have you allowed a discussion on this matter ? What is going on ?

MR. SPEAKER : No, I have not allowed it.

SHRI RAGHU RAMAIAH : In view of the statement made...*(Interruption)*

MR. SPEAKER : Papers to be laid on the Table.

SHRI RAGHU RAMAIAH : He has made a statement and I must say something in defence ; it must be placed on record...... *(interruption)*. He says that they are the real Congress. We are the real Congress... *(interruption)*

12.37 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Report and Review of working of Indian Rare Earths Limited Bombay

THE DEPUTY MINISTER (SHRIMATI NANDINI SATAPATHY) : Sir, on behalf of Shrimati Indira Gandhi. I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :-

(1) Review by the Government on the working of the Indian Rare Earths Limited, Bombay, for the year 1968-69.

(2) Annual Report of the Indian Rare Earths Limited, Bombay, for the year 1968-69, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See* No. LT—1981/69.]

Papers under Tariff Commission Act, 1951

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA RADDY) : Sir, on behalf of Shri Fakhruddin Ali Ahmed, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under sub-section (2) of section 16 of the Tariff Commission Act, 1951 :

(1) (i) Report (1968) of the Tariff Commission on the fixation of fair selling prices of Automobiles.

(ii) Government Resolution No. 1(58)/68-A. E. Ind. (1) dated the 4th October, 1969 on the